संपादकीय जागरण

मंगलवार, 28 अगस्त, 2018 : भाद्रपद कृष्ण 2 वि. 2075

अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है

ईवीएम के खिलाफ दुष्प्रचार

निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव सुधारों पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने मत पत्र से चुनाव कराने की जो मांग की उसे गैर जरूरी मांग के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा लगता है कि कुछ विपक्षी दलों ने जनता के मन में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के प्रति संशय पैदा करने की ठान ली है। शायद यही कारण है कि उनकी ओर से ऐसे सवाल उछाले गए कि खराब ईवीएम से केवल भाजपा को ही वोट क्यों जाते हैं? इस सवाल का कोई जवाब इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि यह सवाल ही एक दुष्प्रचार का हिस्सा है। ईवीएम को लेकर कैसे-कैसे दुष्प्रचार होते हैं और किस तरह मीडिया का एक हिस्सा भी उसमें शामिल होता है, इसका एक उदाहरण पिछले साल उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों के दौरान तब मिला था जब सहारनपुर की एक निर्दलीय प्रत्याशी इस सफेद झूठ के साथ सामने आई थी कि उसके हिस्से में तो खुद उसके घरवालों के ही वोट नहीं दर्ज हुए। उसकी शिकायत को सही मानकर खूब हवा दी गई, लेकिन यह सामने आते ही सबको सांप सूंघ गया कि उसे 87 वोट हासिल हुए हैं। एक दुष्प्रचार तो दिल्ली विधानसभा में ही किया गया था। आखिर कौन भूल सकता है कि खुद को इंजीनियर बताने वाले एक विधायक ने किस तरह ईवीएम सरीखे एक खिलौने के जरिये यह साबित करने का स्वांग किया था कि इस मशीन के जरिये वोट इधर-उधर किए जा सकते हैं? सभी को याद होगा कि इन इंजीनियर साहब के साथ-साथ अन्य दलों के प्रतिनिधि किस तरह ईवीएम से छेड़छाड़ करने की निर्वाचन आयोग की चुनौती को स्वीकार करने से पीछे हट गए थे?

यह समझ आता है कि राजनीतिक दल ईवीएम में और सुधार की जरूरत जताएं और एक प्रतिशत से अधिक वोटों की जांच की मांग करें, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि वे आगामी आम चुनाव मत पत्र से कराने पर जोर दें। यह तो एक तरह से देश को बैलगाड़ी युग में ले जाने वाली मांग है। क्या विपक्षी दल इससे परिचित नहीं कि मत पत्र से मतदान के दौरान किस तरह बड़े पैमाने पर धांधली होती थी? यदि वे भूल गए हैं तो हाल में पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनावों का स्मरण करें, जब तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मत पत्र लूटने के साथ मतपेटियां तालाबों और कुओं में फेंक दी थीं। आखिर यह ढिठाई नहीं तो और क्या है कि निर्वाचन आयोग के समक्ष तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि मत पत्र सुरक्षित हैं और साफ-सुथरे चुनाव प्रक्रिया में उनका बहुत योगदान है। ईवीएम को बदनाम करने के पहले विपक्षी दल यह याद रखें तो बेहतर कि दिल्ली, बिहार, पंजाब आदि राज्यों के विधानसभा चुनाव और हाल के कई उपचुनावों के नतीजे इसी मशीन से ही निकले हैं? समस्या केवल यह नहीं कि ईवीएम को संदिग्ध बताया जा रहा है, बल्कि यह भी है कि निर्वाचन आयोग की साख पर प्रहार किया जा रहा है। आयोग के बारे में राहुल गांधी का ताजा कथन दुष्प्रचार की राजनीति का हिस्सा ही नजर आता है।

पोल खोलतीं सड़कें

चंद रोज की बारिश ने सड़कों का जो खस्ताहाल कर दिया, वह तंत्र की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर सवाल है। राजधानी लखनऊ की अंदरूनी सड़कों से लेकर राजमार्ग तक गड्ढों में तब्दील हो गए हैं और जो अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। निर्माण टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी विकास के साथ सड़कों की निर्माण लागत भी कई गुना बढ़ गई है। जाहिर है कि आम आदमी से कर के रूप में अर्जित बड़ी धनराशि सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर खर्च की जा रही है। यद्यपि सड़कों का मौजूदा हाल देखकर यह यकीन करना कठिन है कि संबंधित एजेंसियों द्वारा यह कार्य ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। लखनऊ की सड़कों को हांडी का चावल मानकर परखें तो अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रदेश की बाकी सड़कों का क्या हाल होगा। शहर की शायद ही कोई सड़क है जिस पर खतरनाक गड्ढे न हों। वैसे सूबे में सड़कों की असली सूरत देखनी हो तो सबसे बेहतरीन सड़कों में शुमार लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर सफर करिए। इसकी बदहाली से अनुमान लगाया जा सकता है कि सड़क निर्माण के नाम पर जनता के धन की किस तरह बर्बादी की जा रही है। टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर में यह तर्क अस्वीकार्य है कि बारिश के कारण सड़कें बह गईं।

सूबे में सड़कों की असली सूरत देखनी हो तो बेहतरीन सड़कों में शुमार लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर सफर करिए

सड़कों की दुर्गति के मामले सीधे-सीधे घटिया निर्माण की परिणति है। सड़कों का घटिया निर्माण कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं है। आम-ओ-खास लोग इसकी वजह भी जानते हैं, पर आमतौर पर राजमार्गों के निर्माण में ऐसा नहीं होता था। मौजूदा परिदृश्य निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों की मिलीभगत एवं दुस्साहस की इंतिहा है। राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यह आवश्यक है कि अभियान चलाकर सभी सड़कों का ऑडिट कराया जाए ताकि इनके घटिया निर्माण कार्य की पूरी असलियत सामने आ सके।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या रक्षा सामग्री के मोर्चे पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए?

आज का सवाल

क्या कुछ विपक्षी दलों के इस आरोप में दम है कि एक साथ चुनाव से लोकतंत्र कमजोर होगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

खतरे में मुक्त व्यापार व्यवस्था

डॉ. भरत झुनझुनवाला

अमेरिका का मुक्त व्यापार से पीछे हटना यह बताता है कि अब वहां नई तकनीकों का सृजन कम हो रहा और वह अन्य देशों से मुकाबला करने में असफल हो रहा है

एक समय अमेरिका विश्व व्यापार संगठन यानी डब्लूटीओ की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभा रहा था, लेकिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसी डब्लूटीओ को नुकसानदेह बता रहे हैं। इसे समझने के लिए पहले मुक्त व्यापार के सिद्धांत को समझें। यह सिद्धांत यही है कि हर एक क्षेत्र किसी खास वस्तु के उत्पादन में महारत रखता है। जैसे भुसावल में केले का उत्पादन सस्ता पड़ता है और मेरठ में चीनी का। दोनों के लिए लाभप्रद है कि भुसावल केले का उत्पादन करके मेरठ को भेजे और मेरठ चीनी का उत्पादन कर उसे भुसावल भेजे। इससे दोनों को केला और चीनी सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन अब दूसरी स्थिति को समझें, जिसमें अमेरिका लड़ाकू विमान सस्ता बनाता है और भारत दूध का उत्पादन सस्ता करता है। मुक्त व्यापार के सिद्धांत के अनुसार अमेरिका को लड़ाकू विमानों का निर्यात करना चाहिए और भारत को दूध का। अब मान लीजिए कि अमेरिका लड़ाकू विमानों का दुनिया में इकलौता उत्पादक है और उसके एवज में वह मनचाहा दाम चाहता है। ऐसे में भारत के हित में यही होगा कि वह अपने देश में ही लड़ाकू विमान बनाए।

मुक्त व्यापार का सिद्धांत तब नाकाम हो जाता है जब किसी विशेष देश का किसी माल पर एकाधिकार होता है जैसे लड़ाकू विमान के मामले में अमेरिका का है। 1990 के दशक में अमेरिका में नए तकनीकी आविष्कार हो रहे थे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सॉफ्टवेयर बनाया, सिस्को ने राउटर सिस्टम बनाए, एचपी ने प्रिंटर इत्यादि बनाए। अमेरिका इन एकाधिकार वाली वस्तुओं को दुनियाभर में बेचना चाहता था। तब उसके लिए मुक्त विश्व व्यापार दोहरे लाभ का सौदा था। एक तरफ विंडोज सॉफ्टवेयर जैसे एकाधिकार वाले माल को अमेरिका मुंहमांगे दाम पर बेचकर दुनियाभर से लाभ कमाता था। दूसरी ओर भारत से सस्ती चीनी का आयात करके लाभ उठाता था। इसीलिए अमेरिका ने उस समय मुक्त व्यापार की जोरशोर से पैरवी की और डब्लूटीओ को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले कुछ समय में हालात बदल गए हैं। अब विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर, सिस्को के राउटर या प्रिंटर जैसे माल तमाम देश बनाने लगे हैं। अमेरिका के पास एकाधिकार वाले उत्पाद कम रह गए हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए विश्व व्यापार घाटे का सौदा हो गया है। एकाधिकार वाली वस्तुओं की संख्या कम होने से उसके पास महंगा माल बेचने के आज कम अवसर हैं। अब अमेरिका की स्थिति भुसावल और मेरठ जैसी हो गई है। अमेरिका सेब का उत्पादन करके भारत को भेज सकता है और भारत चीनी का उत्पादन कर अमेरिका को भेज सकता है।

इस प्रकार का विश्व व्यापार वास्तव में दोनों देशों के लिए लाभप्रद है, लेकिन इस स्थिति में अमेरिका और भारत के श्रमिकों के वेतन भी बराबर हो जाएंगे। जैसे अमेरिका में सेब के उत्पादन में यदि श्रमिक की दिहाड़ी 6,000 रुपये है और भारत के कुल्लू में श्रमिक की दिहाड़ी 400 रुपये है तो भारत का सेब अमेरिका के मुकाबले सस्ता पड़ेगा और अमेरिका का सेब भारत में नहीं बिक पाएगा।

अवधेश राजपूत

खुले विश्व व्यापार का तार्किक परिणाम यह होगा कि संपूर्ण विश्व में वेतन भी बराबर होंगे। यदि ऐसा होता है तो विकसित देशों के वर्तमान में ऊंचे वेतन नीचे आएंगे जो अमेरिका को स्वीकार नहीं हैं। इसलिए अमेरिका चाहता है कि अब यह विश्व व्यापार से पीछे हट जाए जिससे भारत का सस्ता सेब और सस्ती चीनी, अमेरिका में प्रवेश न करे और अमेरिका के सेब उत्पादक अपने श्रमिकों को पहले की ही तरह ऊंचा वेतन देते रहें। इसी सोच के तहत अमेरिका ने बीते दिनों भारत और चीन से आयात होने वाले इस्पात पर भारी आयात कर लगाया। भारत में इस्पात का उत्पादन सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहां श्रमिकों के वेतन कम हैं। ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले इस्पात पर आयात कर इसलिए बढ़ाए ताकि अमेरिका के इस्पात उत्पादकों का धंधा चौपट न होने पाए। अमेरिका का मुक्त व्यापार से पीछे हटना यह बताता है कि अब वहां नई तकनीकों का सृजन कम हो रहा है। अमेरिका को मुक्त व्यापार में अब विश्व के तमाम देशों से टक्कर लेनी पड़ रही है जिसमें वह असफल हो रहा है। अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्लूटीओ को ही खंडित करने की रणनीति बना ली है। डब्लूटीओ के नियमों में व्यवस्था है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी देश किसी विशेष माल पर आयात कर लगा सकता है। इस प्रावधान का उपयोग करते हुए अमेरिका ने भारत में उत्पादित इस्पात पर आयात कर बढ़ाया, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस्पात के उत्पादन में राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई पेंच नहीं है।

अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मनचाही मात्रा में इस्पात का उत्पादन कर सकता है। उसके लिए भारत से इस्पात के आयात का कोई संकट पैदा नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ढाल के रूप में उपयोग करते हुए भारत से आयातित इस्पात पर आयात कर बढ़ा दिया। उन्होंने एक कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है जिसके अंतर्गत डब्लूटीओ के नियमों के बावजूद अमेरिकी सरकार उत्पादों पर मनचाहे आयात कर लगा सकेगी। डब्लूटीओ संधि करते समय सभी देशों ने अपने द्वारा लगाए जाने वाले अधिकतम आयात कर की सीमा निर्धारित कर दी थी। अब ट्रंप ने नया कानून बनाकर उस संधि को पलटने की योजना बनाई है। यदि अमेरिका ने पूर्व में डब्लूटीओ को आश्वासन दे रखा है कि वह किसी विशेष उत्पाद पर एक सीमा तक ही आयात कर लगाएगा तो अब वह उससे ज्यादा आयात कर लगाने के लिए डब्लूटीओ की मूल भावना के विपरीत कानून बनाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्लूटीओ की भावना के खिलाफ एक और कदम उठाया है। डब्लूटीओ में देशों के बीच कोई विवाद उठने पर उसकी अपील डब्लूटीओ की अपीलीय व्यवस्था में की जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपीलीय व्यवस्था में नए जजों की नियुक्ति पर सहमति नहीं दी है। वहां जजों की संख्या कम होती जा रही है और शीघ्र ही अपीलीय व्यवस्था में एक भी जज नहीं रह जाएगा। ऐसे में अपीलीय व्यवस्था निरस्त हो जाएगी और डब्लूटीओ के दायरे में विवादों को हल करने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। तब अमेरिका समेत हर देश खुलकर डब्लूटीओ के नियमों का उल्लंघन कर सकेगा, क्योंकि इस मामले में अपील ही नहीं हो पाएगी।

वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने सही कदम उठाते हुए तमाम देशों को आमंत्रित किया था कि डब्लूटीओ पर नई पहल की जाए, लेकिन भारत अथवा किसी दूसरे विकासशील देश द्वारा की गई इस पहल का सफल होना लगभग असंभव है। इसका कारण यह है कि विश्व व्यापार मूलतः विकसित देशों के लिए अब उतना लाभदायक नहीं रह गया है। विश्व अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्व में श्रम के एक ही वेतन की ओर बढ़ रही है जो कि विकसित देशों को स्वीकार नहीं है। इसलिए विश्व अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार के अंत की आशंका ही अधिक दिखती है।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

हर घर तक पहुंचने वाला बैंक

भारत जैसे विशाल देश में किसी केंद्रीय सत्ता के 50 माह का कालखंड बहुत छोटा माना जाएगा, लेकिन जब चुनौती बड़ी हो और दांव पर देश का वर्तमान एवं भविष्य, दोनों ही हों तो सरकार में कम समय में ही ईमानदारी के साथ साहसिक निर्णय लेने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं एक ऐसी ही सरकार का अंग हूं। हर गरीब, किसान और उपेक्षित व्यक्ति तक बैंकों की सुविधा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार एक नया बैंक-इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) शुरू करने जा रही है। इस बैंक के शुरू होने के साथ ही डाकिया बैंक की सुविधा हर घर तक पहुंचा देगा। बैंकिंग सुविधा की इस होम डिलिवरी के जरिये सरकार समाज में हाशिये पर खड़े आखिरी व्यक्ति को वित्तीय मुख्यधारा में शामिल करने में सफल होगी।

संचार मंत्रालय पिछली सरकार के एक दशक के कार्यकाल के अविश्वास, अनिर्णय, आरोपों के दौर से आगे निकल चुका है। जनता परिणामोन्मुखी सरकार चाहती थी और हमने ऐसा ही करके दिखाया है। सभी भारतीय नागरिकों को जनधन खाते से जोड़ने के सफल कार्यक्रम के बाद राजग सरकार अब बैंकिंग सेवाओं को जनता के घर तक पहुंचाने जा रही है। देश के कोने-कोने में मौजूद डाककर्मी इस कार्य को अंजाम देंगे। डाकिया सरकार का वह प्रतिनिधि होता है जो जनता के सुख-दुःख से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। उसकी पहुंच हर नागरिक तक होती है, भले ही वह कैसी भी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का हो या कैसे ही दुर्गम स्थान पर रहता हो।

जनधन योजना, यूनिक पहचान पत्र आधार, मोबाइल और पोस्टल पेमेंट्स बैंक यानी जे यू एम और पी को मिला दें तो जंप बनता है। इस जंप से आर्थिक मोर्चे पर वास्तव में एक ऐसी उछाल आने वाली है जिससे हर नागरिक बैंकिंग सेवाओं से जुड़ जाएगा। यह एक ऐसी सामाजिक क्रांति का आगाज है, जो अंततः सभी भारतीयों को एक साझा वित्तीय, आर्थिक और डिजिटल धरातल पर ले आएगी। बैंकिंग सेवाओं की कार्यप्रणाली को जो लोग जटिल समझकर दूर रहते थे, आइपीपीबी उन लोगों तक भी बैंकिंग सेवा पहुंचाने का एक प्रबल प्रयास है। यह एक सस्ता, सुरक्षित और सरल डिजिटल भुगतान ढांचा भी प्रदान करेगा, जिससे प्रत्येक भारतीय डिजिटल मेनस्ट्रीम का हिस्सा बन सके। यह बैंक वित्तीय सेवा कार्यप्रणाली को सुविधाजनक और सर्वसुलभ बनाने के लिए डाककर्मी की प्रत्यक्ष सहायता भी उपलब्ध कराएगा। इसकी पूरी कार्यप्रणाली हाशिये पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक वित्तीय समावेशन को पहुंचाने में आने वाली सभी बाधाओं से रहित है। पोस्ट ऑफिस के वर्तमान खाताधारकों को भी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सुविधा स्वतः मिल जाएगी। इस बैंक से ऐसे वित्तीय परिवेश के विकास में सहायता मिलेगी जो डिजिटल होगा। इस बैंक की कार्यप्रणाली ग्राहकोन्मुखी और ग्राहक सेवा के अनुभव को अच्छा रखने पर केंद्रित होगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वर्तमान पोस्टल व्यवस्था और नई तकनीक का सर्वाधिक इस्तेमाल करके बैंकिंग सुविधा की पहुंच को कई गुना बढ़ा देगा। अभी देश में जो बैंकिंग ढांचा है उसमें बैंकिंग शाखाओं का एक तिहाई और एटीएम बूथों का लगभग छठा हिस्सा ही ग्रामीण भारत में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कार्यशील होने के बाद यह परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। इसके 1.50 लाख से अधिक सुविधा केंद्रों में से 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण भारत में होंगे। इसके 2.50 लाख से अधिक एजेंट बैंकिंग सुविधा को हर घर तक पहुंचाएंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक विश्व का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क होगा जो विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देगा।

मनोज सिन्हा

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सक्रिय होते ही देश में ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या 49,000 से बढ़कर 1,30,000 हो जाएगी

डाकिया जब बैंकर की भूमिका निभाएगा तो वह बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और अल्पबैंकिंग सुविधाओं वाले लाखों भारतीयों को वित्तीय सेवा मुहैया कराएगा।

आइपीपीबी का समग्र उद्देश्य आम जनता के लिए सबसे अधिक पहुंच वाला, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनना है। यह सरकार केवित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करेगा। यह बैंक विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा जिनमें बचत एवं चालू खाते, धन अंतरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बिल एवं जनोपयोगी भुगतान और उद्यम एवं व्यापार संबंधी भुगतान शामिल है। आइपीपीबी द्वारा तीसरे पक्ष की तरफ से भी कई वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें छोटे कर्ज, बीमा, निवेश और डाकघर बचत खाता शामिल हैं। इसके साथ ही डाकिये के पास पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन होगी जिससे ग्राहक मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज, बिजली, पानी एवं गैस आदि के बिल सहित बीमा आदि की किश्तों का भी भुगतान कर सकेंगे। आइपीपीबी के लाभों को जनता तक पहुंचाने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। लोगों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

आइपीपीबी के क्रियाशील हो जाने के बाद मनरेगा में दी जाने वाली मजदूरी, छात्रवृत्तियां, सामाजिक कल्याण योजनाओं और अन्य सरकारी सब्सिडी भी हर ग्राहक तक डाकिये के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकेगी। उद्यमियों और व्यापारियों के लिए भी इस बैंक की सेवाएं उपलब्ध होंगी जिनमें डाक-उत्पाद, ई-कॉमर्स व्यावसायिक उत्पादों की कैश ऑन डिलिवरी का डिजिटल पेमेंट भी संभव हो सकेगा। छोटे दुकानदार, लघु उद्यमियों और असंगठित क्षेत्र के व्यापारी भी इस बैंक से लाभान्वित होंगे। आइपीपीबी के लांच के साथ डाकघरों की 650 शाखाएं और 3,250 सेवा केंद्रों पर इसकी सेवा उपलब्ध होगी। 31 दिसंबर 2018 तक यह बैंक पूरी तरह से डाक विभाग के नेटवर्क का इस्तेमाल करने लगेगा। जिसके दायरे में देश के कोने-कोने में स्थित 1.55 लाख सेवा केंद्र (डाक घर) और तीन लाख से अधिक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं। इसके चलते देश में ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या 49,000 से बढ़कर 1,30,000 हो जाएगी। नई दिल्ली में 1 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय लांच कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जब आइपीपीबी का शुभारंभ करेंगे तब वह वित्तीय समावेशन एवं डिजिटलीकरण की दिशा में भारत के निरंतर बढ़ते कदम का 'मील का पत्थर' होगा। इससे निश्चित रूप से हमारे सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को बल मिलेगा और हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन को वास्तविकता में बदलने की दिशा में गतिशील हो पाएंगे।

(लेखक केंद्रीय संचार राज्य मंत्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मर्यादा

मर्यादा मनुष्य का आभूषण है। जो व्यक्ति मर्यादा का पालन करता है, वह सबसे सुंदर है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन मर्यादा में रहकर ही जीना चाहिए। यदि हम मर्यादापूर्वक अपना जीवन जीएंगे तो हमें कभी कोई कष्ट नहीं होगा और कभी कोई कष्ट आएगा भी तो वह क्षणिक होगा। असल में वह कष्ट नहीं होता, बल्कि तब भगवान हमारे धैर्य और संयम की परीक्षा ले रहे होते हैं। अक्सर हम उचित एवं अनुचित की समझ खो बैठते हैं। यदि उस परिस्थिति में हम अपने प्रण पर अटल रहें और किसी लालच में न फंसें तो भगवान हमसे काफी प्रसन्न होते हैं। तब वे हमारे सभी कष्टों-दुखों को हर लेते हैं।

मर्यादा का मतलब है कि हम उपयुक्त निर्णय लेकर नैतिक व्यवहार करें। आज यदि समाज में दिनों-दिन नैतिकता का पतन होता जा रहा है तो इसका मुख्य कारण मनुष्य का अमर्यादित व्यवहार है। वर्तमान में मनुष्य कानून-व्यवस्था को भंग करने में अपनी शान समझता है, वह बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गया और दूसरों का अपमान करने लगा इसलिए हमारे समाज में तरह-तरह की विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। आग, जल एवं वायु यूं संसार को जीवन प्रदान करती हैं, लेकिन अपनी मर्यादा लांघते ही प्रलयकारी बन जाती हैं, जिसका परिणाम सिर्फ तबाही होता है। हालांकि ऐसा भी मनुष्य के कारण होता है। असल में ईश्वर ने सृष्टि बनाने के साथ उसके नियम भी बनाए, लेकिन मनुष्य ने जब-जब इनका उल्लंघन किया तो किसी न किसी रूप में उसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। मनुष्य सिर्फ सुख चाहता है, लेकिन वह इसकी कीमत नहीं चुकाना चाहता। सुख की चाह रखने वाले मनुष्य को इसकी कीमत भी चुकानी होगी और वह कीमत है मर्यादा।

जब तक मनुष्य अपने आपको लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि विकारों से बचाए रखता है, तब तक वह मर्यादा की सीमा में रहता है। कोई भी मनुष्य तब तक मर्यादित जीवन नहीं जी सकता, जब तक उसमें संतोष का भाव न हो। जब मनुष्य में संतोष का भाव आ जाता है तो फिर उसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं रहता। संतोष से बहुमूल्य कोई धन नहीं हैं। हममें संतोष भाव तभी आएगा, जब हम स्वयं से नहीं कहने की क्षमता विकसित करेंगे और जितनी यह क्षमता विकसित होगी, हम उतने मर्यादित होंगे।

महायोगी पायलट बाबा

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

आतंकवाद और राष्ट्रवाद की बेतुकी तुलना

हृदयनारायण दीक्षित का अपने लेख 'वैचारिक दरिद्रता का प्रदर्शन' में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सतही ज्ञान को 'वैचारिक दरिद्रता' बताना इस मायने में सही है कि उन्हें 'आतंकवाद' और 'राष्ट्रवाद' के बीच के अंतर का न तो अहसास है और न ही सम्यक जानकारी। विदेशी धरती से भारत के स्वयंसेवी संगठन 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' को आतंकी संगठन 'मुस्लिम ब्रदरहुड' के समकक्ष खड़ा करना वास्तव में उनकी उस 'वैचारिक दरिद्रता' का ही प्रदर्शन है, जिससे कांग्रेस भी अचंभित है। वैचारिक मतभेद और वैचारिक अज्ञानता में अंतर होता है। इस दृष्टि से राहुल गांधी का यह कथ्य संघ से वैचारिक मतभेद न होकर उस अज्ञानता को इंगित करने वाला है जिसके वशीभूत होकर उन्होंने आतंकवाद और राष्ट्रवाद की बेतुकी तुलना कर डाली। आखिर राहुल गांधी इस बात को कब समझेंगे कि अब वह केवल एक व्यक्ति मात्र न होकर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के सम्मानित अध्यक्ष हैं। इस दृष्टि से सार्वजनिक मंचों से अभिव्यक्त उनका कोई भी कथ्य उनके निजत्व से ऊपर उठकर समूची कांग्रेस का विचार बन जाता है। ऐसे में यह कहकर भी पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि यह कांग्रेस पार्टी का विचार न होकर राहुल गांधी की निजी वैचारिकता है, क्योंकि वह स्वयं इस समय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। इस स्थिति में क्या यह मान लिया जाय कि कांग्रेस ने भी वैचारिक रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि संघ मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह एक हिंसक आतंकवादी संगठन है? यदि नहीं तो उसे अपने अध्यक्ष पर इस 'वैचारिक दरिद्रता' के लिए क्षमा मांगने हेतु नैतिक दबाव अवश्य बनाना चाहिए।

pandeyvp1960@gmail.com

राजनीति में शुद्धिकरण

राजनीति में शुद्धता व स्वच्छता के लिए सभी दलों को नेक नीति और नीयत से काम करना चाहिए। सभी दलों के प्रमुख नेता अपने-अपने दलों को पाक-साफ बताते हैं, लेकिन हकीकत में दागी हर दल में हैं। जब राजनीतिक पार्टियों में ही अपराधी व दागी होंगे तो देश व समाज में कैसे शुचिता/शुद्धता की बयार बहा सकते हैं। चुनावों में जीत हासिल करने के लिए सभी दल अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देते हैं। राजनीति में शुद्धिकरण के लिए ऐसे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए जो स्वच्छ छवि का हो। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को पहल करनी चाहिए। शुचिता की शुरुआत तो स्वयं ये पार्टियां ही कर सकती हैं। बस जरूरत है तो नेकनीयत व स्वयं के शुद्ध आचरण की।

hemahariupadhyay@gmail.com

दूसरे राज्य भी अपनाएं

आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार हुआ है। अब सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से मुकाबला करते दिख रहे हैं। सरकारी स्कूलों में भी पीटीएम होने लगी है। यह एक अच्छी बात है। इसको बरकरार रखना सरकार का कार्य है। इसी तरह अन्य राज्यों को भी सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए प्रयास करने चाहिए।

आशीष, राम लाल आनंद कॉलेज, दिल्ली विवि

स्कूलों की मनमानी

दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले शिक्षा निदेशालय में जहां पर दसवीं कक्षा में नियमित छात्र के रूप में छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी थी उसमें कुछ छात्र पास नहीं कर पाए। ऐसे में वह दोबारा दसवीं में प्रवेश लेना चाहते हैं लेकिन कुछ स्कूल उनको प्रवेश देने से मना कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन का कहना है कि दसवीं की परीक्षा ओपन स्कूल से पास करने के उपरांत 11वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

विजय कुमार धानिया, नई दिल्ली

एक साथ चुनाव में हर्ज क्या ?

देश में एक साथ चुनाव कराने की ठंडे बस्ते में पड़ी बहस एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। बहरहाल चुनाव आयोग और कुछ विपक्षी दल फिलहाल एक साथ चुनाव के पक्ष में नहीं हैं। सबकी अपनी-अपनी दिक्कत और अपने-अपने विचार हैं, किन्तु एक साथ चुनाव से देश पर आर्थिक बोझ कम होगा, समय की बचत होगी, बारह महीने कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में होने वाले चुनाव से मुक्ति मिलेगी। सरकार निश्चिंत होकर काम कर सकेगी, क्योंकि बार-बार चुनावों से सरकारें और उनके मंत्री सब चुनाव में लग जाते हैं और काम-काज बाधित होता है। आम जनता और सरकारी मशीनरी बार-बार के चुनाव से परेशान भी होती है। इन सब परेशानियों को देखते हुए यदि एक साथ चुनाव पर सहमति बनती है तो यह देशहित में होगा। प्रधानमंत्री की बात को चुनाव आयोग और विपक्ष दोनों को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके लिए यदि कानून बनाना पड़े तो वो भी करना चाहिए। यह बात सही है कि नई व्यवस्था या प्रणाली लागू करने में कुछ परेशानी जरूर होती है, किन्तु भविष्य के लिए यह देश और देशवासियों के साथ ही राजनीतिक पार्टियों के लिए भी बेहतर साबित होगा। इसमें एक दिक्कत सुरक्षा और पूरे देश में एक साथ चुनाव की व्यवस्था करने में कुछ परेशानी आ सकती है। इसके लिए पूरे देश में एक साथ कर्मचारियों की तैनाती और सुरक्षा बलों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसका एक उपाय है कि चुनाव को कई चरणों में बांट दिया जाए। वैसे भी कई राज्यों में पांच-पांच चरणों में मतदान होते ही हैं। एक साथ चुनाव कराने में यदि कुछ लंबा समय लगे तो भी अलग-अलग चुनाव कराने की अपेक्षा बेहतर ही रहेगा।

mahesh_nenava@yahoo.com

ट्वीट-ट्वीट

जब मेजर गोगोई सही थे तब अधिकतर लोगों के उनके खिलाफ होने के बावजूद सेना ने उन्हें अवॉर्ड दिया। जब मेजर गोगोई गलत हैं तो तमाम लोगों के उनके समर्थन में होने के बावजूद सेना उन्हें सजा देगी। इसीलिए मुझे भारतीय सेना पर गर्व है और सर्वाधिक विश्वास भी।

श्वेता सिंह@SwetaSinghAT

देश के खिलाड़ियों को मेडल जीतते देखकर गर्व होता है और जब आप उसके पीछे की वजहों के बारे में सोचते हैं तो खिलाड़ियों की जबरदस्त मेहनत के साथ योगदान ऐसे व्यवहार का भी होता है जब केंद्रीय खेल मंत्री खिलाड़ियों को चाय परोसते नजर आएं। आपने दिल जीत लिया राठौड़ साहब।

सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

भारत में शायद ही कोई अन्य राज्य ऐसा हो जिसे तमाम तरह से और इतना प्यार मिला हो जितना बीते कुछ दिनों में शेष भारत के लोगों द्वारा केरल को मिला है। मुझे मलयाली होने पर गर्व है।

शशि थरूर@ShashiTharoor

एक खिलाड़ी के तौर पर दीपिका पल्लीकल की अपनी अलग पहचान है। उन्होंने एशियाड में अपने देश के लिए कांस्य पदक जीता है। यह उनकी उपलब्धि है जिसमें उनके पति की पहचान जोड़ना क्रिकेट को लेकर हावी हमारी मानसिकता को ही दर्शाता है।

स्मिता बरूआ@smitabarooah

जनपथ

मुख में छूरी हैं धरे अरु जिह्वा पर आग,
केरलवासी सुन रहे रागा जी का राग।
राग़ा जी का राग सदा रहता विद्ध्वंसक,
इसीलिए यह देश आप पर करता है शक।
शामिल होंगे आप नहीं जब सुख में-दुख में,
सत्ता का मिष्ठान जायगा कैसे मुख में!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 29 अंक 42